



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2004/माघ 30, 1925

No. 46]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2004/MAGHA 30, 1925

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

विषय :—परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति-2003
(एन.पी.आर.आर.—2003)

फा. सं. एक्वि 13011/4/2003-एल.आर.डी.—जबकि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति-2003 तैयार की है;

और जबकि भारत सरकार यह चाहती है कि उक्त नीति की विषय-वस्तु को जन-साधारण के ध्यान में लाया जाए तथा इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जाए;

अतः अब यह निदेश दिया जाता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में दी गई राष्ट्रीय नीति को दिनांक 17 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

अनुसूची

विषय :—परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति—2003

अध्याय-I : नीति

प्रस्तावना

1.1 आधारिक संरचनात्मक परियोजनाओं सहित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अनिवार्य अर्जन से लोग विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें अपने घर, परिसम्पत्ति और आजीविका के साधनों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोगों को अपनी भूमि, आजीविका और

संसाधन-आधार से वंचित करने के अलावा, विस्थापन के अन्य घातक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-सांस्कृतिक परिणाम भी सामने आते हैं। भारत सरकार बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन को संभव सीमा तक कम किए जाने की आवश्यकता और जहाँ पर विस्थापन अपरिहार्य हो, वहाँ पर परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास से संबंधित मामलों को अत्यन्त सावधानी से और दूरदर्शिता के साथ सुविचारित रूप से हल किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। ऐसे दृष्टिकोण को जनजातीय लोगों, छोटे और सीमान्त किसानों और महिलाओं के संबंध में विशेष रूप से अपनाए जाने की आवश्यकता है।

1.2 क्षतिपूर्ति करने हेतु नकद भुगतान की प्रणाली होने पर भी, इसके द्वारा अधिकांश मामलों में प्रभावित परिवार, खेती योग्य कृषि भूमि, आवास और अन्य उन संसाधनों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, जिन्हें वे राज्य को समर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कठिनाइयाँ और दुष्कर हो जाती हैं जो अपने जीवन के बने रहने/आजीविका के लिए मुख्य रूप से अर्जित की गयी परिसम्पत्तियों पर निर्भर होते हैं, जैसे भूमिहीन कृषि मजदूर, वन-वासी, काश्तकार और कारीगर। इनके कष्ट और गरीबी ज्यादा गंभीर होती है, फिर भी वे नकद मुआवजे के लिए पात्र नहीं होते हैं।

1.3 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में कुछेक राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की अपनी नीतियाँ और दिशा-निर्देश हैं। तथापि, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में अभी तक कोई राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं की गई है। इस दस्तावेज का आशय नीति के रूप में बुनियादी मानदण्ड और पैकेज निर्धारित करना है जिसे अब इसके बाद परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति-2003 (एन0पी0आर0आर0-2003) कहा जाएगा।

1.4 यह नीति सम्पत्तिहीन ग्रामीण गरीबों को मदद देने, विस्थापित हो चुके संसाधनहीन वर्गों, नामतः छोटे और सीमान्त किसानों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों/ महिलाओं के पुनर्स्थापन संबंधी प्रयासों में सहायता देने की आवश्यकता को अनिवार्य रूप से पूरा करेगी। इसके अलावा, इसका उद्देश्य पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवारों और प्रशासन के बीच कारगर बात-चीत के लिए एक व्यापक आधार मुहैया कराना है। इस प्रकार की बातचीत से लागत संबंधी सुनिश्चितता और विस्थापित व्यक्तियों, विशेष रूप से संसाधनहीन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त ध्यान दिए जाने सहित परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना संभव हो सकेगा। इसका आशय आपसी बात-चीत और वार्ता के लिए अत्यधिक लचीलापन मुहैया कराना है ताकि परिणामस्वरूप तैयार किए जाने वाले पैकेज को सभी प्रभावित व्यक्तियों/ अधिग्रहण निकायों को संतुष्टि प्रदान करने वाले एक व्यावहारिक दस्तावेज के रूप में सभी प्रकार से स्वीकार किया जा सके।

1.5 परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति सभी संबंधित पक्षों के मार्गदर्शन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों और कार्यपालक अनुदेशों के रूप में होगी और यह नीति मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवारों या इससे अधिक परिवारों और पर्वतीय क्षेत्रों, मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी0डी0पी0) वाले खण्डों, भारत के संविधान की अनुसूची-V और अनुसूची-VI में शामिल क्षेत्रों में 250 परिवारों को सामूहिक रूप में विस्थापित करने वाली परियोजनाओं के संबंध में लागू होगी । यह आशा की जाती है कि पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए समुचित सरकार और प्रशासक इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति के अंतर्गत परिकल्पित लाभ परियोजना प्रभावित परिवारों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों सहित संसाधनहीन वर्गों को प्राप्त होते हैं ।

1.6 नीति में प्रस्तावित पुनर्वास अनुदान और अन्य आर्थिक लाभ न्यूनतम होंगे और ये लाभ सभी परियोजना प्रभावित परिवारों, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी0पी0एल0) परिवार हों अथवा गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों से अन्यथा (गैर-बी0पी0एल0) परिवार हों, के लिए लागू होंगे । उन राज्यों, जहाँ पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज, नीति में प्रस्तावित पैकेज से उच्चतर स्तर पर हैं, को अपने पैकेज को लागू करने की स्वतंत्रता है ।

अध्याय-II

2. नीति के उद्देश्य

2.1 नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

- (क) विस्थापन को न्यूनतम करना और गैर-विस्थापन अथवा कम से कम विस्थापन के विकल्प अभिज्ञात करना;
- (ख) जनजातीय लोगों और संसाधनहीन वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने सहित परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की योजना बनाना;
- (ग) परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर जीवन-स्तर मुहैया कराना; तथा
- (घ) अधिग्रहण निकाय और परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग के द्वारा सद्भावपूर्ण सम्बन्ध बनाने को सुसाध्य बनाना ।

अध्याय-III

3. परिभाषाएँ

3.1 इस नीति दस्तावेज में प्रयोग किए गए विभिन्न शब्दों/पदों की परिभाषा निम्नानुसार है:-

(क) "पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासक" का अर्थ है, राज्य सरकार के जिला कलक्टर से अन्यून पद का अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा संबंधित परियोजना में परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया हो, परन्तु यदि परियोजना के संबंध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, तो ऐसी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके की जाएगी।

(ख) परियोजना के संबंध में "प्रभावित क्षेत्र" का अर्थ है, एक ऐसी परियोजना, जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 अथवा किसी अन्य लागू अधिनियम के तहत भूमि अर्जित की जा रही है, के अंतर्गत गावों या इलाके के अंतर्गत शामिल क्षेत्र अथवा परियोजना के जलाशय में पानी एकत्रित होने के कारण डूबने वाले क्षेत्र की समुचित सरकार द्वारा इस नीति के पैरा 5.1 के अंतर्गत घोषणा करना।

(ग) "कृषि परिवार" का अर्थ है, एक ऐसा परिवार, जिसका जीविका चलाने के लिए मुख्य साधन कृषि है और इसमें भू-स्वामियों के परिवार तथा कृषि भूमि पर कृषि करने वाले उप-काश्तकारों, कृषि श्रमिकों, वन भूमि के अधिभोगियों और लघु वन उत्पादों को एकत्रित करने वालों के परिवार शामिल हैं।

(घ) "कृषि श्रमिक" का अर्थ है, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतया प्रभावित क्षेत्र की घोषणा से तत्काल पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए प्रभावित क्षेत्र का निवासी रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि न रखता हो परन्तु अपनी जीविका, मुख्यतः ऐसी घोषणा के तत्काल पूर्व उसमें स्थित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम के द्वारा अर्जित करता हो और जो अपनी जीविका से वंचित हुआ हो।

(ङ) "कृषि भूमि" में वह भूमि शामिल है जिसका प्रयोग निम्न प्रयोजन के लिए किया गया है या किया जा सकता है:-

- (i) कृषि या बागवानी;
- (ii) डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, पशुओं के प्रजनन या पशुपालन तथा ऐसी नर्सरी, जिसमें औषधीय जड़ी-बूटियाँ उगायी जाती हैं;
- (iii) फसलें, घास उगाना या उद्यान उत्पाद प्राप्त करना ; तथा

(iv) वह भूमि जिसे कृषकों द्वारा पशुओं की चराई के लिए प्रयोग में लाया गया है, परन्तु इसमें वह भूमि शामिल नहीं है जिसका प्रयोग केवल लकड़ी की कटाई के लिए किया गया है।

(च) 'समुचित सरकार' का अर्थ है:-

- (i) संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केन्द्रीय सरकार;
- (ii) उस परियोजना के संबंध में जिसका निष्पादन केन्द्र सरकार की एजेंसी/ केन्द्र सरकार के उपक्रम द्वारा किया जाता है अथवा केन्द्र सरकार के आदेशों/निर्देशों पर किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है, केन्द्र सरकार अन्यथा राज्य सरकार, तथा
- (iii) अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार।

(छ) गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी0पी0एल0) परिवार:- गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार वह परिवार होंगे जैसा कि भारत के योजना आयोग द्वारा समय समय पर परिभाषित किया जाता है।

(ज) एक परियोजना के संबंध में 'पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त' का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त जो उस सरकार के आयुक्त/सचिव के पद से नीचे के पद का अधिकारी नहीं होगा;

(झ) "विस्थापित परिवार" का अर्थ है कोई भू-धृति धारी, काश्तकार, सरकारी पट्टेदार या अन्य सम्पत्ति का स्वामी जिसे परियोजना के प्रयोजन हेतु प्रभावित क्षेत्र में, आबादी में स्थित भू-खण्ड सहित उसकी भूमि या अन्य सम्पत्ति का अधिग्रहण किए जाने के कारण ऐसी भूमि या सम्पत्ति से विस्थापित किया गया है;

(ञ) 'परिवार' का अर्थ है परियोजना प्रभावित परिवार जिसमें ऐसा व्यक्ति, उसकी पत्नी/उसका पति, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ, अवयस्क भाई या अविवाहित बहनें, पिता, माता और अन्य सदस्य जो उसके साथ रह रहे हों एवं अपनी जीविका के लिए उस पर निर्भर हों, शामिल हैं।

(ट) 'जोत-क्षेत्र' का अर्थ है किसी एक व्यक्ति द्वारा दखलकार के रूप में या काश्तकार के रूप में अथवा दोनों ही रूपों में धारित कुल भूमि;

(ठ) 'सीमान्त किसान' का अर्थ है एक ऐसा खेतिहर-किसान जिसके पास एक हैक्टेयर तक असिंचित भूमि या आधे हैक्टेयर तक सिंचित भूमि हो;

(ड) 'गैर कृषि श्रमिक' का अर्थ है वह व्यक्ति जो कृषि श्रमिक नहीं है परन्तु जो सामान्यतया प्रभावित क्षेत्र में, उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने से तत्काल पूर्व से कम से कम 3 वर्षों से अन्यून अवधि से रह रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि नहीं रखता हो परन्तु जो इस प्रकार की घोषणा से तत्काल पूर्व में अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रमिक के रूप में या ग्रामीण दस्तकार के रूप में अर्जित करता रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में, अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रम के द्वारा या ऐसे दस्तकार के रूप में अर्जित करने से वंचित हुआ हो ।

(ढ) 'अधिसूचना' का अर्थ है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(ण) 'अधिभोगी' का अर्थ है अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे सदस्य जो 25 अक्टूबर, 1980 से पहले वन भूमि के कब्जाधारी रहे थे ।

(त) 'परियोजना' का अर्थ है एक ऐसी परियोजना जिसमें किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवार या इससे अधिक परिवार और पहाड़ी क्षेत्रों, डी0डी0पी0 वाले खण्डों, भारत के संविधान की अनुसूची-V और अनुसूची-VI में शामिल क्षेत्रों में 250 परिवार या इससे अधिक परिवार सामूहिक रूप में विस्थापित होते हैं ।

(थ) 'परियोजना प्रभावित परिवार' का अर्थ है एक ऐसा परिवार/व्यक्ति जिसका निवास स्थान या अन्य सम्पत्ति या जीविका का साधन परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया के कारण पर्याप्त रूप से प्रभावित हुआ हो और जो प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने की तारीख से पूर्व लगातार तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक उस क्षेत्र में रह रहा हो अथवा जो प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने की तारीख से पूर्व लगातार तीन वर्षों से अन्यून अवधि से प्रभावित क्षेत्र में कोई व्यापार, व्यवसाय या उद्योग-धंधा चला रहा हो ।

(द) परियोजना के संबंध में 'पुनर्स्थापन क्षेत्र' का अर्थ है किसी समुचित सरकार द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए अर्जित किए गए या अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र को इस नीति के पैरा 5.12 के अंतर्गत पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित करना ।

(ध) 'अधिग्रहण निकाय' का अर्थ होगा ऐसी कोई कम्पनी, निगमित निकाय या कोई संस्था या कोई अन्य संगठन जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना है और इसमें समुचित सरकार भी शामिल है यदि भूमि का अर्जन ऐसी सरकार के अपने प्रयोग के लिए किया जाता है या तत्पश्चात् ऐसी भूमि जनहित में

किसी निगमित निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन या किसी कम्पनी को पट्टे, अनुज्ञप्ति के अंतर्गत या ऐसी किसी कम्पनी को भूमि अंतरण की किसी अन्य पद्धति के तहत, जैसा भी मामला हो, आबंटित कर दी जाती है ।

(न) " छोटे किसान " का अर्थ है ऐसा कृषक जिसके पास दो हैक्टेयर तक असिंचित भूमि या एक हैक्टेयर तक सिंचित भूमि हो ।

अध्याय-IV

4. पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियाँ एवं कार्य

4.1 जहाँ समुचित सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जित करने के परिणामस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवार या इससे अधिक परिवार और पहाड़ी क्षेत्रों, डी0डी0पी0 खण्डों, भारत के संविधान की अनुसूची-V और अनुसूची-VI में शामिल क्षेत्रों में 250 परिवार या इससे अधिक परिवार सामूहिक रूप से विस्थापित होते हैं, तो वह राज्य सरकार के जिला कलक्टर से अन्यून पद के अधिकारी को अधिसूचना द्वारा उस परियोजना के संबंध में पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी ।

परन्तु यदि परियोजना के संबंध में समुचित सरकार केन्द्र सरकार है तो ऐसी नियुक्ति केन्द्र सरकार के साथ परामर्श से की जाएगी ।

4.2 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासक की ऐसे अधिकारी और कर्मचारी सहायता करेंगे जिन्हें समुचित सरकार उपलब्ध कराएगी ।

**पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास
के लिए प्रशासक**

4.3 समुचित सरकार तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त के पर्यवेक्षण , निर्देशों तथा नियंत्रण के अध्यक्षीन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक संबंधित परियोजना में सभी परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए सभी उपाय करेगा ।

4.4 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना तैयार करने तथा इसे कार्यान्वित करने के संबंध में समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य प्रशासक, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास में निहित होगा ।

**प्रशासक की शक्तियाँ
और कार्य**

4.5 समुचित सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यक्षीन पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक निम्नलिखित कार्यों/कर्तव्यों को पूरा करेगा:-

- (i) व्यक्तियों के विस्थापन को न्यूनतम करना और अधिग्रहण निकाय के साथ परामर्श से गैर-विस्थापन या कम से कम विस्थापन किए जाने के विकल्पों को अभिज्ञात करना;
- (ii) पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजना तैयार करते समय परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ परामर्श करना;
- (iii) परियोजना से प्रतिकूलतः प्रभावित अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के परिवारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- (iv) इस नीति के पाँचवें अध्याय के तहत यथा अपेक्षित पुनर्स्थापन तथा

पुनर्वास योजना/स्कीम का प्रारूप तैयार करना;

- (v) परियोजना प्रभावित परिवारों तथा अधिग्रहण निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की जाती है, के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से भूमि अर्जन के विभिन्न संघटकों, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास कार्यक्रमों या कार्यक्रमों के अनुमानित व्यय सहित बजट तैयार करना;
- (vi) परियोजना के लिए तथा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी समुचित भूमि अर्जित करना ।
- (vii) परियोजना प्रभावित परिवारों को भूमि आबंटित करना तथा लाभ स्वीकृत करना;
- (viii) ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा सौंपे जाएं।

प्रशासक की शक्तियों का प्रत्यायोजन

4.6 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक, इस नीति के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत उसे प्रदत्त की गई प्रशासनिक शक्तियों और सौंपे गए कर्तव्यों को, लिखित रूप में आदेश के द्वारा तहसीलदार से अन्यून पद के किसी अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

4.7 इस नीति के तहत समुचित सरकार द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी तथा कर्मचारी पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक के अधीनस्थ कर्मचारी होंगे ।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए आयुक्त

4.8 राज्य सरकार ऐसी परियोजनाओं, जिनके लिए यह नीति लागू होती है, के संबंध में पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास हेतु उस सरकार के आयुक्त/सचिव से अन्यून पद के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी जिसे पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त कहा जाएगा ।

4.9 इस नीति के प्रयोजनों के लिए, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, जिन्हें परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया है, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त के अधीनस्थ होंगे ।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त के कार्य

4.10 आयुक्त, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाएँ/स्कीमें तैयार करने, ऐसी योजनाओं/स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने तथा इस नीति के अध्याय-VII में उल्लेख किए गए अनुसार शिकायतों को दूर करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

अध्याय-V

5. पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजनाएँ:

इस अध्याय में उल्लेख की गई प्रक्रिया का प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करने, परियोजना प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण तथा गणना करने तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का आकलन करने, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजना का प्रारूप तैयार करने तथा इसे अंतिम रूप से प्रकाशन के लिए अनुसरण किया जाएगा ।

प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करना 5.1 समुचित सरकार यदि उसका यह मत हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जित किए जाने से मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवारों अथवा इससे अधिक परिवारों तथा पहाड़ी क्षेत्रों, डी0डी0पी0 वाले खण्डों, भारत के संविधान की अनुसूची-V और अनुसूची-VI में शामिल क्षेत्रों में 250 परिवारों या इससे अधिक परिवारों के सामूहिक रूप से विस्थापित होने की संभावना है तो वह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके गाँवों या उस इलाके के क्षेत्र को परियोजना के प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है और तब संबंधित परियोजना के संबंध में इस नीति के वर्ण्य विषय लागू होंगे ।

परियोजना प्रभावित परिवारों आदि के सर्वेक्षण तथा संगणना के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 5.2 इस नीति के पैरा 5.1 के तहत की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, उनमें से एक समाचार पत्र स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिसका परिचालन उन गाँवों या क्षेत्रों में भी होता हो, जिनके प्रभावित होने की संभावना है और अधिसूचना की प्रति संबंधित ग्राम पंचायतों के सूचना बोर्ड पर तथा प्रभावित क्षेत्र में अन्य प्रमुख स्थान या स्थानों पर भी लगायी जानी चाहिए ।

5.3 नीति के पैरा 5.1 के तहत जब एक बार घोषणा कर दी जाती है तब पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक परियोजना के द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों और परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य आरंभ करेगा ।

5.4 प्रत्येक सर्वेक्षण में परियोजना प्रभावित परिवारों के बारे में निम्नलिखित रूप से गाँव-वार सूचना दी जाएगी:-

- (i) परिवार के वे सदस्य जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहते हैं, कोई व्यापार, व्यवसाय या कार्य करते हैं;
- (ii) परियोजना प्रभावित वे परिवार जिनके अपने घर, कृषि भूमि, रोजगार से वंचित होने अथवा अपने व्यापार, व्यवसाय या कार्य के मुख्य स्रोत से पूर्णतः या पर्याप्त रूप से अलग होने की संभावना है।
- (iii) कृषि श्रमिक या गैर-कृषि श्रमिक।
- (iv) वे परियोजना प्रभावित परिवार जिनके कब्जे में 25 अक्टूबर, 1980 से पूर्व अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले से वन भूमि रही है।

5.5 पैरा 5.4 के अंतर्गत आरंभ किए गए प्रत्येक सर्वेक्षण को पैरा 5.1 के तहत की गई घोषणा की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

5.6 ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार, नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक, उसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के ब्यौरे के प्रारूप को परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित लोगों की आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना के द्वारा और किसी भी अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा ताकि प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों तक ये ब्यौरे पहुँच सकें।

5.7 सर्वेक्षण के ब्यौरे के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर और इस संबंध में उन्हें प्राप्त हुई आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक अपनी सिफारिशों के साथ सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरे को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

5.8 राज्य सरकार, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक की सिफारिशों के प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर राजपत्र में सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरे को प्रकाशित करेगी।

5.9 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना प्रभावित परिवारों को मुख्यतया समूह या समूहों में बसाया जाए और ऐसे बसावट स्थल जहाँ तक संभव हो मौजूदा ग्राम पंचायत का ही एक भाग बनने चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि परियोजना प्रभावित परिवारों को मेजबान समुदाय के साथ समानता तथा आपसी मेल-मिलाप के आधार पर तथा प्रत्येक समूह की अपनी पहचान तथा संस्कृति को बनाए रखने की इच्छा के अनुरूप बसाया जाए।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए उपलब्ध भूमि का निर्धारण

5.10 उपर्युक्त पैरा 5.9 के प्रयोजनों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए ऐसे भू-खण्डों की सूची तैयार करेगा जो किसी भी मौजूदा ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो सकती है।

5.11 पैरा 5.10 के तहत सूचीबद्ध की गई भूमि में निम्नलिखित भूमि शामिल होगी:-

(क) सरकारी बंजरभूमि या सरकार के स्वामित्व में कोई अन्य भूमि जो परियोजना प्रभावित परिवारों को आबंटित करने के लिए उपलब्ध हो।

(ख) यदि वहाँ पर सरकारी भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी स्कीम/योजना के प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि। तथापि, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि के ऐसे अर्जन से परियोजना प्रभावित परिवारों की एक अन्य सूची न तैयार हो जाए।

पुनर्स्थापन क्षेत्र की घोषणा

5.12 समुचित सरकार परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए अर्जित किए गए किसी क्षेत्र या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को अधिसूचना के द्वारा पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित करेगी।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए भूमि अर्जित करने की शक्ति

5.13 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक, समुचित सरकार की ओर से उपर्युक्त पैरा 5.11(ख) की विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत किसी भूमि को या तो अनिवार्यतः अर्जित कर सकता है अथवा किसी भी व्यक्ति की सहमति से उसकी भूमि खरीद सकता है और इस प्रयोजन के लिए एक करार कर सकता है।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजना का प्रारूप

5.14 पैरा 5.3 और 5.11 में उल्लेख किए गए अनुसार पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए मूल रूप से सर्वेक्षण एवं परियोजना प्रभावित परिवारों की गणना का कार्य तथा पुनर्स्थापन के लिए भूमि की आवश्यकता का आकलन पूरा करने के पश्चात् पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक महिलाओं सहित परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों, उन निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं, जिनके अंतर्गत परियोजना क्षेत्र स्थित है, के अध्यक्षों के साथ परामर्श से परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजना का प्रारूप तैयार करेगा।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए निधियों का प्रबंधन 5.15 प्रारूप स्कीम/योजना तैयार करते समय, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास स्कीम/योजना की लागत उस परियोजना की लागत का अभिन्न भाग होना चाहिए जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है और परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास हेतु पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभों के लिए सम्पूर्ण व्यय तथा अन्य व्यय का वहन, उस अधिग्रहण निकाय द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है ।

5.16 परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की स्कीम/योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अधिग्रहण निकाय का होगा ।

5.17 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक उसके अधिकार के अंतर्गत सौंपी गई निधियों के संबंध में लेखों के समुचित खाते और रिकार्ड रखेगा तथा इस संबंध में समुचित सरकार को आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा ।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की स्कीम/योजना के प्रारूप की विषय-वस्तु 5.18 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास हेतु तैयार की गई प्रत्येक प्रारूप स्कीम/योजना में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, नामतः:-
(क) परियोजना के लिए अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा संबंधित गाँव (गाँवों) का नाम ।

(ख) परियोजना प्रभावित परिवारों की गाँव-वार सूची तथा परिवार-वार विस्थापित व्यक्तियों की संभावित संख्या, भूमि का क्षेत्रफल तथा उसका स्वरूप तथा उनके स्वामित्व के तहत अचल सम्पत्ति का ब्यौरा जिसमें प्रभावित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित ऐसी सम्पत्ति की सर्वेक्षण संख्या दी गई हो ।

(ग) ऐसे क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की सूची तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनकी आजीविका कृषि संबंधी कार्यकलापों पर निर्भर है ।

(घ) ऐसे व्यक्तियों की सूची जो परियोजना के लिए भूमि अर्जित किए

जाने के परिणामस्वरूप अपना रोजगार या अपनी आजीविका खो चुके हैं या खोने वाले हैं अथवा जो अपने पेशे या व्यवसाय के मुख्य स्रोतों से पूर्णतः अथवा अधिकांशतः वंचित हो गए हैं ।

(ड) दखलकारों की सूची, यदि कोई हो;

(च) सार्वजनिक उपयोग वाले या सरकारी भवनों की सूची जिनके प्रभावित होने की संभावना है ।

(छ) परियोजना प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराये जाने वाले लाभों तथा पैकेज की विस्तृत सूची;

(ज) उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल का ब्यौरा जिसे परियोजना प्रभावित परिवारों को आवास क्षेत्र में पुनर्स्थापन के लिए तथा भूमि आबंटित करने के लिए अर्जित किया जा सकता है;

(झ) मूलभूत तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा जिन्हें पुनर्स्थापन के लिए उपलब्ध कराया जाना है ।

(ञ) विस्थापित परिवारों को हटाने तथा पुनर्स्थापन क्षेत्रों में उन्हें पुनर्स्थापित करने की समयावधि;

(ट) ऐसा कोई अन्य ब्यौरा जिसे पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक विस्थापित व्यक्तियों की सूचना के लिए शामिल करना उपयुक्त समझता है ।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी स्कीम/योजना का अंतिम रूप से प्रकाशन

5.19 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी स्कीम/योजना के प्रारूप को राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा । इसे अनुमोदित करने से पूर्व अधिग्रहण निकाय की सहमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा । प्रारूप स्कीम/योजना को प्रभावित क्षेत्र में इसके व्यापक प्रचार के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

5.20 स्कीम/योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद यह स्कीम/योजना लागू हो जाएगी ।

अध्याय-VI

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ

- 6.1 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास (आर० एण्ड आर०) संबंधी लाभों को परियोजना प्रभावित सभी परिवारों, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले (बी०पी०एल०) परिवार हों अथवा गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों से अन्यथा (गैर-बी०पी०एल०) परिवार हों, को उपलब्ध कराया जाएगा ।
- 6.2 ऐसा कोई भी परियोजना प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर हो और जिसका घर अधिगृहीत कर लिया गया हो, को अधिगृहीत घर के क्षेत्र की वास्तविक क्षति के बराबर आवास स्थल बिना किसी लागत के आबंटित किया जा सकेगा, परन्तु यह आवास स्थल ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग मीटर भूमि तथा शहरी क्षेत्र में 75 वर्ग मीटर भूमि से अधिक नहीं होगा ।
- 6.3 गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को घर के निर्माण के लिए एक ही बार दी जाने वाली सहायता के रूप में 25000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी । गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से अन्यथा परिवार (गैर-बी०पी०एल० परिवार) यह सहायता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे ।
- 6.4 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि रही हो और जिसकी पूरी भूमि अर्जित कर ली गई हो, को भूमि के क्षेत्र की वास्तविक क्षति के बराबर कृषि भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि आबंटित की जाएगी, परन्तु यह भूमि अधिकतम एक हैक्टेयर सिंचित भूमि या दो हैक्टेयर असिंचित भूमि/ कृषि योग्य बंजर भूमि होगी, बशर्ते कि जिलों में सरकारी भूमि उपलब्ध हो ।
- 6.5 पंजीकरण के लिए अदा की जाने वाली स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्कों को अधिग्रहण निकाय द्वारा वहन किया जाएगा ।
- 6.6 पैरा 6.4 के तहत आबंटित की गई भूमि सभी प्रकार के ऋण-भारों से मुक्त होगी । आबंटित की गई भूमि परियोजना प्रभावित परिवार में पत्नी और पति के संयुक्त नाम से आबंटित की जाएगी ।
- 6.7 अर्जित की गई भूमि के बदले में बंजर भूमि/ अवक्रमित भूमि आबंटित किए जाने के मामले में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि विकसित करने के लिए 10000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाएगी । कृषि भूमि आबंटित किए जाने के मामले में कृषि उत्पादन के लिए प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में 5000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.8 पशु रखने वाले प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को पशुशाला का निर्माण करने के लिए 3000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.9 प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भवन निर्माण सामग्री, अपने सामान तथा पशुओं को प्रभावित क्षेत्र से पुनर्स्थापन क्षेत्र तक ले जाने के लिए परिवहन लागत के रूप में 5000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.10 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसमें ग्रामीण दस्तकार/ छोटे व्यापारी तथा स्व-नियोजित व्यक्ति शामिल हों, को कार्य शैड/ दुकान के निर्माण के लिए एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.11 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि हो तथा जिसकी पूरी भूमि अर्जित की गई हो, जिन मामलों में परियोजना प्रभावित परिवार को न तो कृषि भूमि आबंटित की गई हो और न ही उसके किसी एक सदस्य को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, को "आजीविका की क्षति" के लिए 750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.12 प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि रखने वाले ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी पूरी भूमि अर्जित नहीं की गई है और भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप वे सीमान्त किसान बन गए हैं, को 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.13 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि हो तथा जो भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप छोटे किसान बन गए हों, को 375 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.14 "कृषि श्रमिक" या "गैर-कृषि श्रमिक" की श्रेणी से संबंधित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, को 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.15 प्रत्येक विस्थापित परियोजना प्रभावित परिवार, को एक वर्ष की अवधि के लिए 250 दिनों तक प्रति मास 20 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक आजीविका भत्ता दिया जाएगा ।

6.16 आपातकालीन स्थिति जैसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत अथवा किसी अन्य प्रवृत्त अधिनियम के सदृश्य उपबंध के तहत भूमि के अर्जन के मामले में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक की अवधि के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा । ऐसे परिवारों को उपर्युक्त पैरों में उल्लेख किए गए अनुसार, नीति के तहत पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ भी दिए जाएंगे ।

6.17 लम्बी दूरी में भूमि क्षेत्र का अर्जन: रेलवे लाइनों, राजमार्गों, ट्रान्समिशन

लाइनों, पाइप लाइन बिछाने जैसी परियोजनाओं के मामले में, जिनमें भूमि का अर्जन कम चौड़ाई में कई किलोमीटर की दूरी में किया जाता है, परियोजना प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रह राशि मुहैया करायी जाएगी और उनके लिए कोई अन्य पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ मुहैया नहीं कराये जाएंगे ।

6.18 परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभों के एक भाग के रूप में पुनर्स्थापन क्षेत्र में स्व-रोजगार परियोजनाएं आरंभ करने हेतु उद्योग-धंधा चलाने का कौशल विकसित करने हेतु अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाएँ मुहैया करायी जाएंगी ।

6.19 उन परियोजना प्रभावित परिवारों•जिनके कब्जे में 25 अक्टूबर, 1980 से पहले से वन भूमि थी, को इस नीति के तहत उपर्युक्त पैरों में दिए गए अनुसार सभी पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ दिए जाएंगे ।

6.20 अनुसूचित जाति वर्ग के परियोजना प्रभावित परिवार, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण की सुविधा प्राप्त थी, पुनर्स्थापन क्षेत्र में भी आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

6.21 अनुसूचित जनजाति वर्ग के परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ

6.21.1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी ।

6.21.2 जनजातीय वर्ग का प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार इस नीति के तहत उपर्युक्त पैरों में उल्लिखित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा ।

6.21.3 जनजातीय वर्ग के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को वन उत्पादों के संबंध में परंपरागत अधिकार/उपयोग से वंचित होने के एवज में 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

6.21.4 परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों को उनके प्राकृतिक बसावट के निकट ही किसी संहत खण्ड में पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई तथा सांस्कृतिक पहचान को कायम रख सकें ।

6.21.5 परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों को सामुदायिक तथा धार्मिक अवसर पर सभाओं के लिए भूमि निःशुल्क दी जाएगी ।

6.21.6 परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों, जिन्हें जिला/तालुक से बाहर पुनर्स्थापित किया जाता है, को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ मौद्रिक रूप में 25% अधिक दिए जाएंगे ।

6.21.7 भूमि अन्तरण के संबंध में लागू नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करके किये गए जनजातीय भूमि के अन्तरण को निष्प्रभावी माना जाएगा तथा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ केवल भूमि के जनजातीय मूल के स्वामी को दिए जाएंगे ।

6.21.8 परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे जनजातीय परिवार जिन्हें नदी,

तालाब, बाँध में मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त था, को जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा ।

6.21.9 परियोजना प्रभावित वे जनजातीय परिवार, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, पुनर्स्थापन क्षेत्र में भी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

6.22 पुनर्स्थापन क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाने वाली बुनियादी सुविधाएँ :-

6.22.1 प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्स्थापन क्षेत्र में स्थानान्तरित करते समय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक जहाँ तक संभव हो, निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:-

(क) यदि किसी गाँव/क्षेत्र की स्थानान्तरित की जाने वाली पूरी जनता किसी विशेष समुदाय से संबंध रखती है, तो ऐसे लोगों/ परिवारों को सुसंहत क्षेत्र में सामूहिक रूप से पुनः बसाया जाए ताकि विस्थापित परिवारों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों (सामाजिक मेल-मिलाप) में कोई बाधा न आए ।

(ख) अनुसूचित जातियों के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें गाँवों के निकट स्थानों पर पुनः बसाया जाता है ।

6.22.2 परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन स्थल पर बुनियादी सुविधाएँ तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएँ समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध करायी जाएंगी । यह वांछनीय है कि पेयजल, बिजली, विद्यालयों, औषधालयों की व्यवस्था और अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्स्थापन स्थलों पर पहुँचने की व्यवस्था को भी पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक द्वारा तैयार की गई पुनर्स्थापन योजना में शामिल किया जाए ।

अध्याय-VII

7. विवाद निवारण तंत्र

- विवाद निवारण तंत्र** 7.1 परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समिति
- 7.1.1 ऐसी प्रत्येक परियोजना जिसके लिए यह नीति लागू की जाती है, के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की स्कीम/योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार उस परियोजना के प्रशासक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जिसे पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समिति कहा जाएगा ।
- 7.1.2 ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार गठित की गई पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समिति में अन्य सदस्यों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा;
- (i) प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का एक प्रतिनिधि
 - (ii) प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का एक-एक प्रतिनिधि;
 - (iii) स्वयंसेवी संगठन का एक प्रतिनिधि;
 - (iv) प्रमुख बैंक का एक प्रतिनिधि;
 - (v) प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रही पंचायती राज संस्थाओं का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति;
 - (vi) प्रभावित क्षेत्र में शामिल क्षेत्र के संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य
- 7.1.3 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समिति के कार्यों, इसकी बैठकों तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों को विनियमित करने की प्रक्रिया का निर्धारण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा ।
- 7.2 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ**
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** 7.2.1 ऐसी प्रत्येक परियोजना, जिसके लिए यह नीति लागू की जाती है, के संबंध में राज्य सरकार परियोजना प्रभावित परिवारों की शिकायतों के निवारण के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करेगी ।

7.2.2 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का संघटन, शक्तियाँ, कार्य तथा इसके कार्यकरण से संबंधित अन्य मामले समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे ।

7.2.3 यदि किसी परियोजना प्रभावित परिवार को यह शिकायत हो कि उसे इस नीति के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार यथा स्वीकार्य पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ नहीं दिये जा रहे हैं तो वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में उपयुक्त याचिका दायर कर सकता है ।

7.2.4 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराने के लिए फार्म तथा पद्धति और वह समयावधि जिसके भीतर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है तथा उसके निपटान की समयावधि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी ।

7.2.5 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए परियोजना स्तर पर प्रशासक/ पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति के निर्णय के विरुद्ध पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में सभी शिकायतों पर विचार करने तथा उनका निपटान करने और ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक को ऐसे निर्देश देने जिन्हें उचित समझा जाता है, की शक्ति प्राप्त होगी ।

अन्तर्राज्यीय परियोजनाएँ

7.3 अन्तर्राज्यीय परियोजनाएँ :-

7.3.1 यदि परियोजना के तहत एक से अधिक राज्य या राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेश का ऐसा क्षेत्र शामिल है, जहाँ पर परियोजना प्रभावित परिवार रहते हैं या रहते थे अथवा उन्हें वहाँ पर पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो केन्द्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) संबद्ध राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, के साथ परामर्श से इस नीति के प्रयोजनों के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति करेगा ।

7.3.2 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी योजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन के तरीके पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा आपस में विचार किया जाएगा और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक द्वारा यथा सम्मत एक सामान्य योजना/स्कीम इस नीति में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचित की जाएगी ।

7.3.3 यदि स्कीमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई आती है तो इस मामले को केन्द्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) को उसके निर्णय के लिए अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्र सरकार का निर्णय संबद्ध राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बाध्यकारी होगा ।

अध्याय-VIII

निगरानी तंत्र

8. राष्ट्रीय निगरानी समिति

राष्ट्रीय निगरानी समिति

8.1 केन्द्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग उन सभी परियोजनाओं के संबंध में, जिनके लिए यह नीति लागू होती है, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी के लिए भूमि संसाधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन करेगा । इस समिति के सदस्य निम्नलिखित अधिकारी या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अन्यून पद के अधिकारी होंगे:-

सचिव, योजना आयोग
सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सचिव, जल संसाधन मंत्रालय
सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
सचिव, रेल मंत्रालय
सचिव, विद्युत मंत्रालय
सचिव, कोयला मंत्रालय

इसके अलावा, [redacted] परियोजना, जिसके लिए भूमि अर्जित की जानी है, के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को इसके सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा । समिति के कार्यों और कर्तव्यों को इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

8.2 राष्ट्रीय निगरानी समिति को सेवाएं उन सभी परियोजनाओं के संबंध में, जिनके लिए यह नीति लागू होती है, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी जाएंगी ।

**राष्ट्रीय निगरानी
प्रकोष्ठ**

8.3 इस नीति के तहत गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पद का अधिकारी होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है निगरानी प्रकोष्ठ की सहायता अनुबंध-I में उल्लिखित अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।

8.4 प्रयोज्यता

प्रयोज्यता

परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति (एन0पी0आर0आर0-2003) भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुबंध-I

**राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ का संघटन
(देखें पैरा 8.3)**

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या
1	संयुक्त सचिव, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास	1
2	क्षेत्रीय निदेशक/ इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ/ परामर्शदाता	4
3	उप निदेशक	4
4	सांख्यिकीय अधिकारी	1
5	अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	1
6	सहायक	2
7	सांख्यिकीय सहायक	2
8	अवर श्रेणी लिपिक एवं टंकक	4
9	आशुलिपिक	9
10	चपरासी	4
11	सफाई कर्मचारी	2
12	ड्राईवर	2

ललिता कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**(Department of Land Resources)****RESOLUTION**

New Delhi, the 17th February, 2004

Subject :—National Policy on Resettlement and Rehabilitation for Project Affected Families—2003 (NPRR—2003)

F. No. Acq. 13011/4/2003-LRD.—WHEREAS the Government of India, Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya), Department of Land Resources (Bhumi Sansadhan Vibhag), has formulated a National Policy on Resettlement and Rehabilitation for Project Affected Families—2003;

AND whereas the Government of India desires that the contents of the said Policy be brought to the notice of the general public and given widest publicity;

NOW therefore, it is directed that the National Policy given in the Schedule hereto annexed be published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section 1, dated 17th February, 2004.

SCHEDULE

Subject :—National Policy on Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families—2003

CHAPTER – I: POLICY**PREAMBLE:**

1.1 Compulsory acquisition of land for public purpose including infrastructure projects displaces people, forcing them to give up their home, assets and means of livelihood. Apart from depriving them of their lands, livelihoods and resource-base, displacement has other traumatic psychological and socio-cultural consequences. The Government of India recognizes the need to minimize large scale displacement to the extent possible and, where displacement is inevitable, the need to handle with utmost care and forethought issues relating to Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families. Such an approach is especially necessary in respect of tribals, small & marginal farmers and women.

1.2 The system of extending cash compensation does not, by itself, in most cases, enable the affected families to obtain cultivable agricultural land, homestead and other resources which they have to surrender to the State. The difficulties are more acute for persons who are critically dependent on the acquired assets for their subsistence/ livelihoods, such as landless agricultural workers, forest dwellers, tenants and artisans, as their distress and destitution is more severe, and, yet they are not eligible for cash compensation.

1.3 Some States and Central Ministries/Departments have their own Policies and Guidelines for Resettlement and Rehabilitation. However, a National Policy on Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families (PAFs) has not so far been enunciated. This Document aims at

laying down basic norms and packages in the shape of a Policy which would, henceforth be referred to as the National Policy on the Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families - 2003 (NPRR-2003).

1.4 The Policy essentially addresses the need to provide succour to the assetless rural poor, support the rehabilitation efforts of the resource poor sections, namely, small and marginal farmers, SCs/STs and women who have been displaced. Besides, it seeks to provide a broad canvas for an effective dialogue between the Project Affected Families and the Administration for Resettlement & Rehabilitation. Such a dialogue is expected to enable timely completion of projects with a sense of definiteness as regards costs and adequate attention to the needs of the displaced persons especially the resource poor sections. The intention is to impart greater flexibility for interaction and negotiation so that the resultant Package gains all-round acceptability in the shape of a workable instrument providing satisfaction to all stakeholders/ Requiring Bodies.

1.5 The National Policy on the Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families will be in the form of broad guidelines and executive instructions for guidance of all concerned and will be applicable to Projects displacing 500 families or more enmasse in plain areas and 250 families enmasse in hilly areas, Desert Development Programme (DDP) blocks, areas mentioned in Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India . It is expected that the appropriate Government and Administrator for R&R shall implement this Policy in letter and spirit in order to ensure that the benefits envisaged under the Policy reaches the Project Affected Families, especially resource poor sections including SCs/STs.

1.6 The rehabilitation grants and other monetary benefits proposed in the Policy would be minimum and applicable to all project affected families whether belonging to BPL or non-BPL families. States where R&R packages are higher than proposed in the Policy are free to adopt their own packages.

CHAPTER - II

2. OBJECTIVES OF THE POLICY

2.1 The objectives of the Policy are as follows:-

- (a) To minimize displacement and to identify non-displacing or least-displacing alternatives;
- (b) To plan the resettlement and rehabilitation of Project Affected Families, (PAFs) including special needs of Tribals and vulnerable sections;
- (c) To provide better standard of living to PAFs; and
- (d) To facilitate harmonious relationship between the Requiring Body and PAFs through mutual cooperation.

CHAPTER - III

3. DEFINITIONS

3.1 The Definition of various terms used in this Policy Document are as follows:

(a) "Administrator for Resettlement and Rehabilitation" means an officer not below the rank of District Collector of the State Government appointed by it for the purpose of resettlement and rehabilitation of the Project Affected Families of the Project concerned provided that if the appropriate Government in respect of the project is the Central Government, such appointment shall be made in consultation with the Central Govt.

(b) "affected zone", in relation to a project, means declaration under para 5.1 of this Policy by the appropriate Government area of villages or locality under a project for which the land is being acquired under Land Acquisition Act, 1894 or any other Act in force or an area that comes under submergence due to impounding of water in the reservoir of the project;

(c) "agricultural family" means a family whose primary mode of livelihood is agriculture and includes family of owners as well as sub-tenants of agricultural land, agricultural labourers, occupiers of forest lands and of collectors of minor forest produce;

(d) "agricultural labourer" means a person normally resident in the affected zone for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected zone who does not hold any land in the affected zone but who earns his livelihood principally by manual labour on agricultural land therein immediately before such declaration and who has been deprived of his livelihood;

(e) "agricultural land" includes lands used or capable of being used for the purpose of-

(i) agriculture or horticulture;

(ii) dairy farming, poultry farming, pisciculture, breeding or livestock and nursery growing medical herbs;

(iii) raising of crops, grass or garden produce; and

(iv) land used by an agriculturist for the grazing of cattle, but does not include land used for cutting of wood only;

(f) "appropriate Government" means,-

(i) in relation to acquisition of land for the purposes of the Union, the Central Government;

(ii) in relation to a project which is executed by Central Government agency/Central Government undertaking or by any other agency on the orders/directions of Central Government, the Central Government, otherwise the State Government and

(iii) in relation to acquisition of land for other purposes, the State Government.

(g) 'BPL Family': The Below Poverty Line Families shall be those as defined by the Planning Commission of India from time to time.

(h) "Commissioner for Resettlement and Rehabilitation", in relation to a project, means the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation appointed by the State Government not below the rank of Commissioner/Secretary of that Government.

(i) "Displaced family" means any tenure holder, tenant, Government lessee or owner of other property, who on account of acquisition of his land including plot in the abadi or other property in the affected zone for the purpose of the project, has been displaced from such land or other property;

(j) "family" means Project Affected Family consisting of such persons, his or her spouse, minor sons, unmarried daughters, minor brothers or unmarried sisters, father, mother and other members residing with him and dependent on him for their livelihood.

(k) "holding" means the total land held by a person as an occupant or tenant or as both;

(l) "marginal farmer" means a cultivator with an unirrigated land holding upto one hectare or irrigated land holding upto half hectare;

(m) "non-agricultural labourer" means a person who is not an agricultural labourer but is normally residing in the affected zone for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected zone and who does not hold any land under the affected zone but who earns his livelihood principally by manual labour or as a rural artisan immediately before such declaration and who has been deprived of earning his livelihood principally by manual labour or as such artisan in the affected zone;

(n) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(o) "occupiers" means members of Scheduled Tribe community in possession of forest land prior to 25th October, 1980;

(p) "project" means a project displacing 500 families or more enmasse in plain areas and 250 families or more enmasse in hilly areas, DDP blocks, areas mentioned in Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India as a result of acquisition of land for any project.

(q) "project affected family" means a family/person whose place of residence or other properties or source of livelihood are substantially affected by the process of acquisition of land for the project and who has been residing continuously for a period of not less than three years preceding the date of declaration of the affected zone or practicing any trade, occupation or vocation continuously for a period of not less than three years in the affected zone, preceding the date of declaration of the affected zone.

(r) "Resettlement zone", in relation to a project, means the declaration of any area under Para 5.12 of this Policy by the appropriate Government acquired or proposed to be acquired for resettlement and rehabilitation of Project Affected Families as a resettlement zone ;

(s) "Requiring Body" shall mean any company, a body corporate, an institution, or any other organization for whom land is to be acquired by the appropriate Government, and includes the appropriate Government if the acquisition of land is for such Government either for its own use or for subsequent allotment of such land in public interest to a body corporate, institution, or any other organization or to any company under lease, license or through any other system of transfer of land to such company, as the case may be.;

(t) "small farmer" means a cultivator with an unirrigated land holding up to two hectares or with an irrigated land holding up to one hectare.

CHAPTER - IV**4. APPOINTMENT OF ADMINISTRATOR AND COMMISSIONER FOR RESETTLEMENT AND REHABILITATION AND THEIR POWERS & FUNCTIONS**

4.1 Where the appropriate Government is satisfied that acquisition of land for any project involves displacement of 500 families or more enmasse in plain areas and 250 families or more enmasse in hilly areas, DDP blocks, areas mentioned in Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India as a result of acquisition of land for any project, it shall, by notification, appoint in respect of that project, an officer not below the rank of District Collector of the State Government to be the Administrator for R&R in respect of that project.

Provided that if the appropriate Government in respect of the project is the Central Government, such appointment shall be made in consultation with the Central Government.

4.2 The Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall be assisted by such officers and employees as the appropriate Government may provide.

**Administrator
For
Resettlement
&
Rehabilitation**

4.3 Subject to the superintendence, directions and control of the appropriate Government and Commissioner for R&R, the Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall take all measures for the rehabilitation and resettlement of all project affected families(PAF) in respect of that project.

4.4. The overall control and superintendence of the formulation of resettlement and rehabilitation plan and execution of the same shall vest in the Administrator, Resettlement & Rehabilitation.

**Powers and
Functions of
Administrator**

4.5 Subject to any general or special order of the appropriate Government, the Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall perform the following functions/duties:-

- (i) minimize displacement of persons and identify non-displacing or least displacing alternatives in consultation with the requiring body ;
- (ii) hold consultation with the project affected families while preparing a resettlement and rehabilitation scheme/ plan;
- (iii) ensure that interest of the adversely project affected families of Scheduled Tribes and weaker sections are protected.

(iv) prepare a draft plan/ scheme of resettlement and rehabilitation as required under Chapter V of this Policy;

(v) prepare a budget including estimated expenditure of various components of acquisition of land, resettlement and rehabilitation activities or programmes in consultation with representatives of the project affected families and requiring body for whom the land is acquired;

(vi) acquire adequate land for the project and also for settling the project affected families;

(vii) allot land and sanction benefits to project affected families;

(viii) perform such other functions as the appropriate Government may, from time to time, by order in writing, assign.

Delegation of powers of Administrator

4.6 Administrator for Resettlement & Rehabilitation may, by order in writing, delegate such of the administrative powers conferred and duties imposed on him by or under this Policy to any officer not below the rank of Tehsildar or equivalent.

4.7 All officers and staff appointed by the appropriate Government under this Policy shall be subordinate to the Administrator for Resettlement & Rehabilitation.

Commissioner for R & R

4.8 The State Government shall appoint an officer of the rank of Commissioner/Secretary of that Government for resettlement and rehabilitation in respect of such projects to which this Policy applies to be called the Commissioner for Resettlement & Rehabilitation.

4.9 For the purposes of this Policy, the Administrator for Resettlement & Rehabilitation and other officers and employees appointed for the purposes of resettlement and rehabilitation of PAF shall be subordinate to the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation.

Functions of Commissioner for R&R

4.10 The Commissioner shall be responsible for supervising the formulation of resettlement and rehabilitation plans/schemes, proper implementation of such plans/schemes and redressal of grievances as mentioned in Chapter VII of this Policy.

CHAPTER – V

5. SCHEMES/PLANS FOR RESETTLEMENT AND REHABILITATION:

The procedure mentioned in this Chapter shall be followed for declaration of Affected Zone, carrying out survey & census of Project Affected Families, Assessment of Government land available and land to be acquired for the purpose of Resettlement and Rehabilitation, preparation of draft scheme/ plan for R&R and its final publication.

Declaration of Affected Zone

5.1 The appropriate Government may, if it is of the opinion that acquisition of land for a project is likely to displace 500 families or more enmasse in plain areas and 250 families or more in hilly areas, DDP blocks, areas mentioned in Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India declare, by notification in the Official Gazette, area of villages or localities as an affected zone of the project and thereupon the contents of this Policy shall apply to the project involved.

Procedure to be followed for survey and census of PAFs etc.

5.2 Every declaration made under Para 5.1 of the Policy shall be published in at least two daily newspapers one of them should be in the local vernacular having circulation in villages or areas which are likely to be affected and also by affixing a copy of the notification on the Notice Board of the concerned Gram Panchayats and other prominent place or places in the affected zone.

5.3 Once the declaration is made under para 5.1 of the Policy, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall undertake a survey for identification of the persons and their families likely to be affected by the project.

5.4 Every survey shall contain the following village-wise information of the project affected families:-

(i) members of families who are permanently residing, practicing any trade, occupation or vocation in the project affected area;

(ii) Project Affected Families who are likely to lose their house, agricultural land, employment or are alienated wholly or substantially from the main source of their trade occupation or vocation.

(iii) Agricultural labourers and non-agriculture labourers.

(iv) Project Affected Families who are having possession of forest lands prior to 25th October, 1980, that is prior to the commencement of the Forest (Conservation) Act, 1980.

5.5 Every survey undertaken under Para 5.4 shall be completed within a period of ninety days from the date of declaration made under para 5.1.

5.6 On the expiry of the period of ninety days as aforesaid, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall, by notification, and also in such other manner so as to reach all persons likely to be affected, publish a draft of the details of the findings of the survey conducted by him for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby.

5.7 On the expiry of thirty days from the date of publication of the draft of the details of survey and after considering the objections and suggestions received by him in this behalf, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall submit the final details of survey with his recommendations to the State Government.

5.8 Within forty-five days from the date of receipt of the recommendations of the Administrator for Resettlement & Rehabilitation, the State Government shall publish the final details of survey in the Official Gazette.

5.9 The Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall ensure that the Project Affected Families may be settled preferably in group or groups and such sites should form a part of existing gram panchayat as far as possible. However, it has to be ensured that the PAFs may be resettled with the host community on the basis of equality and mutual understanding, consistent with the desire of each group to preserve its own identity and culture.

**Assessment
of land
available for
R&R**

5.10 For the purposes of para 5.9 above, the Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall draw up a list of lands which may be available in any existing Gram Panchayat for resettlement and rehabilitation of project affected families.

5.11 The lands drawn up under para 5.10 shall consist of :-

(a) Government waste lands and any other land vesting in the Government available for allotment to project affected families.

(b) If sufficient Government land is not available there, then land to be acquired for the purposes of resettlement and rehabilitation scheme/plan. However, the Administrator for R&R should ensure that such acquisition of land should not lead to another list of affected families.

Declaration of Resettlement Zone	5.12 The appropriate Government shall, by notification, declare any area acquired or proposed to be acquired for resettlement and rehabilitation of project affected families, as a resettlement zone.
Power to acquire land for R&R	5.13 The Administrator for R&R, on behalf of the the appropriate government, may either compulsorily acquire keeping in view the contents of Para 5.11(b) above any land under the Land Acquisition Act, 1894 or purchase land from any person through consent award and may enter into an agreement for this purpose.
Draft Scheme/ Plan for R&R	5.14 After completion of base line survey and census of Project Affected Families and assessment of requirement of land for resettlement as mentioned in Paras 5.3 & 5.11, the Administrator for R&R shall prepare a draft scheme/plan for the Resettlement & Rehabilitation of the Project Affected Families in consultation with representatives of Project Affected Families including women, Chairpersons of elected Panchayati Raj Institutions within which the Project area is situated.
Management of Funds for R&R	5.15 While preparing a draft scheme/Plan, the Administrator for R&R shall ensure that the cost of R&R scheme/Plan should be an integral part of the cost of the Project for which the land is being acquired and the entire expenditure of R&R benefits and other expenditure for resettlement and rehabilitation of PAFs are to be borne by the requiring body for which the area is being acquired. 5.16 It shall be the responsibility of the requiring body to provide sufficient funds to the Administrator for R&R for proper implementation of resettlement & Rehabilitation scheme/plan of Project Affected Families. 5.17 The Administrator for R&R shall keep proper books of accounts and records of the funds placed at his disposal and submit periodical returns to the Appropriate Government in this behalf.
Contents of Draft Scheme/Plan of R&R	5.18 Every draft scheme/Plan of resettlement and rehabilitation prepared shall contain the following particulars, namely:- (a) the extent of area to be acquired for the project and the name(s) of the corresponding village(s).

(b) a village-wise list of project affected families and likely number of displaced persons, family-wise and the extent and nature of land and immovable property in their possession indicating the survey numbers thereof held by such persons in the affected zone;

(c) a list of agricultural labourers in such area and the names of such persons whose livelihood depend on agricultural activities;

(d) a list of persons who have lost or are likely to lose their employment or livelihood or who have been alienated wholly and substantially from their main sources of occupation or vocation consequent to the acquisition of land for the project;

(e) a list of occupiers, if any,

(f) a list of public utilities and Government buildings which are likely to be affected;

(g) a comprehensive list of benefits and packages which are to be provided to project affected families;

(h) details of the extent of land available which may be acquired in settlement area for resettling and allotting of land to the project affected families;

(i) details of the basic amenities and infrastructure facilities which are to be provided for resettlement;

(j) the time schedule for shifting and resettling the displaced families in resettlement zones;

(k) such other particulars as the Administrator for Resettlement & Rehabilitation may think fit to include for the information of the displaced persons.

**Final
Publication of
Scheme/Plan
of R&R**

5.19 The Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall, submit the draft scheme/plan for R&R to the State Government for its approval. It will be the responsibility of the State Government to obtain the consent of requiring body before approving the same. The draft scheme/plan may be published in the Official Gazette to give wide publicity to the same in the affected zone.

5.20 Upon notification of a scheme/plan, the same shall come into force.

CHAPTER - VI**R&R BENEFITS FOR PROJECT AFFECTED FAMILIES**

6.1 The resettlement and rehabilitation (R&R) benefits shall be extended to all the Project Affected Families (PAF) whether belonging to below poverty line (BPL) or non-BPL.

6.2 Any Project Affected Family (PAF) owning house and whose house has been acquired may be allotted free of cost house site to the extent of actual loss of area of the acquired house but not more than 150 sq.m. of land in rural areas and 75 sq.meter. of land in urban areas.

6.3 Each PAF of BPL category shall get a one-time financial assistance of Rs. 25000/- for house construction. Non-BPL families shall not be entitled to receive this assistance.

6.4 Each PAF owning agricultural land in the affected zone and whose entire land has been acquired may be allotted agricultural land or cultivable waste land to the extent of actual land loss subject to a maximum of one hectare of irrigated land or two hectares of un-irrigated land/cultivable waste land subject to availability of government land in the districts.

6.5 Stamp duty and other fees payable for registration shall be borne by the requiring body.

6.6 The Land allotted under para 6.4 shall be free from all encumbrances. The Land allotted may be in the joint names of wife and husband of PAF.

6.7 In case of allotment of wasteland/degraded land in lieu of acquired land, each PAF shall get financial assistance of Rs. 10000/- per hectare for land development. In case of allotment of agricultural land, a one-time financial assistance of Rs. 5000/- per PAF for agricultural production shall be given.

6.8 Each PAF having cattle shall get financial assistance of Rs. 3000/- for construction of cattle shed.

6.9 Each PAF shall get financial assistance of Rs. 5000/- as transportation cost for shifting of building materials, belongings and cattle etc. from the affected zone to the resettlement zone.

6.10 Each PAF comprising of rural artisan/small trader and self employed person shall get one-time financial assistance of Rs. 10,000/- for construction of working shed/shop.

6.11 Each PAF owning agricultural land in the affected zone and whose entire land has been acquired shall get one-time financial assistance equivalent to 750 days minimum agricultural wages for "loss of livelihood" where neither agricultural land nor regular employment to one member of the PAF has been provided.

6.12 Each PAF owning agricultural land in the affected zone and whose entire land has not been acquired and consequently he becomes a marginal farmer shall get one time financial assistance equivalent to 500 days minimum agricultural wages.

6.13 Each PAF owning agriculture land in the affected zone and who consequently becomes a small farmer shall get one time financial assistance equivalent to 375 days minimum agricultural wages.

6.14 Each PAF belonging to the category of 'agricultural labourer', or 'non-agricultural labourer' shall be provided a one time financial assistance equivalent to 625 days of the minimum agricultural wages.

6.15 Each displaced PAF shall get a monthly subsistence allowance equivalent to 20 days of minimum agricultural wages per month for a period of one year upto 250 days of MAW.

6.16 In the case of acquisition of land in emergent situation such as under Section 17 of the Land Acquisition Act 1894 or similar provision of other Act in force, each PAF shall be provided with transit accommodation, pending resettlement and rehabilitation scheme. Such families shall also get R&R benefits as mentioned in above paras under the Policy.

6.17 Acquisition of Long Stretches of Land: In case of projects relating to Railway Lines, Highways, Transmission Lines and laying pipelines wherein only a narrow stretch of land extending over several kilometers is being acquired, the Project Affected Families will be offered an ex-gratia amount of Rs. 10,000/- per family, and no other Resettlement & Rehabilitation benefits shall be available to them.

6.18 The Project Affected Families shall be provided necessary training facilities for development of entrepreneurship to take up self-employment projects at the resettlement zone as part of R&R benefits.

6.19 The Project Affected Families who were in possession of forest lands prior to 25th October, 1980 shall get all the benefits of R & R as given in above paras under the Policy.

6.20 The PAFs of Scheduled Caste category enjoying reservation benefits in the affected zone shall be entitled to get the reservation benefits at the resettlement zone.

6.21 R&R BENEFITS FOR PROJECT AFFECTED FAMILIES OF SCHEDULED TRIBES.

6.21.1 Each Project Affected Family of ST category shall be given preference in allotment of land.

6.21.2 Each tribal PAF shall be entitled to get R&R benefits mentioned in above Paras under the Policy.

6.21.3 Each Tribal PAF shall get additional financial assistance equivalent to 500 days minimum agriculture wages for loss of customary rights/usages of forest produce.

6.21.4 Tribal PAFs will be re-settled close to their natural habitat in a compact block so that they can retain their ethnic, linguistic and cultural identity.

6.21.5 Tribal PAFs shall get land free of cost for community & religious gathering.

6.21.6 Tribal PAFs resettled out of the district/taluka will get 25% higher R&R benefits in monetary terms.

6.21.7 The Tribal Land Alienated in violation of the laws and regulations in force on the subject would be treated as null and void and the R&R benefits would be available only to the original tribal land owner.

6.21.8 The Tribals families residing in the Project Affected Areas having fishing rights in the river/pond/dam shall be given fishing rights in the reservoir area.

6.21.9 Tribal PAFs enjoying reservation benefits in the affected zone shall be entitled to get the reservation benefits at the resettlement zone.

6.22 BASIC AMENITIES TO BE PROVIDED AT RESETTLEMENT ZONE:

6.22.1 While shifting the population of the Affected Zone to the Resettlement Zone, the Administrator for R&R may as far as possible, ensure that :

a) In case the entire population of the village/area to be shifted belongs to a particular community, such population/families may be resettled enmasse in a compact area so that socio-cultural relations (social harmony) amongst shifted families are not disturbed

b) In case of resettlement of Scheduled Castes PAFs, it may be ensured that they are resettled in sites close to the villages.

6.22.2 The Project Affected Families shall be provided the basic amenities and infrastructural facilities at the resettlement site as per norms specified by the Appropriate Govt. It is desirable that provision of drinking water, electricity, schools, dispensaries and access to the resettlement sites amongst others be included in the resettlement plan formulated by the Administrator for R&R.

CHAPTER - VII

7. DISPUTE REDRESSAL MECHANISM

7.1 R&R COMMITTEE AT PROJECT LEVEL

Dispute Redressal Mechanism

7.1.1 In respect of every project to which this Policy applies, the State Government shall constitute a Committee under the Chairmanship of the Administrator of that Project to be called the Resettlement and Rehabilitation Committee to monitor and review the progress of implementation of scheme/ plan of resettlement and rehabilitation of the Project Affected Families.

7.1.2 The Resettlement & Rehabilitation Committee constituted as above shall inter-alia include as one of its members:-

- (i) a representative of women residing in the affected zone;
- (ii) a representative each of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes residing in the affected zone;
- (iii) a representative of a voluntary organization;
- (iv) a representative of the lead bank;
- (v) Chairman or his nominee of the PRIs located in the affected zone
- (vi) MPs/MLAs of the area included in the affected zone

7.2.3 Procedure regulating the business of the Resettlement & Rehabilitation Committee, its meeting and other matters connected thereto shall be prescribed by the Appropriate Government.

7.2. GRIEVANCE REDRESSAL CELL:

Grievance Redressal Cell

7.2.1 In respect of every project to which this Policy applies, the State Government shall constitute a Grievance Redressal Cell under the Chairmanship of the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation for redressal of grievances of the PAFs.

7.2.2 The composition, powers, functions and other matters relating to the functioning of the Grievance Redressal Cell shall be such as may be prescribed by the Appropriate Government.

7.2.3 Any Project Affected Family, if aggrieved, for not being offered the admissible R&R benefits as provided under this Policy, may move an appropriate petition for redressal of his grievances to the Grievance Redressal Cell.

7.2.4 The form and manner in which and the time within which complaints may be made to the Grievance Redressal Cell and disposed of shall be such as may be prescribed by the appropriate Government.

7.2.5 The Grievance Redressal Cell shall have the power to consider and dispose of all complaints relating to resettlement and rehabilitation against the decision of the Administrator/R&R Committee at Project level for Resettlement & Rehabilitation and issue such directions to the Administrator for Resettlement & Rehabilitation as it may deem proper for the Redressal of such grievances.

7.3 INTER-STATE PROJECTS:

Inter-State Projects

7.3.1 In case a project covers an area in more than one State or States or a Union territory where the project affected families are or had been residing, or proposed to be resettled, the Central Government in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources) shall in consultation with concerned States or Union territory, as the case may be, appoint the Administrator for Resettlement & Rehabilitation and the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation for the purposes of this Policy.

7.3.2 The method of implementation of plans/ schemes for resettlement and rehabilitation shall be mutually discussed by the State Governments and the Union territory administration and the common plan/ scheme shall be notified by the Administrator for Resettlement & Rehabilitation in the State or Union territory administration, as agreed to, in accordance with the procedure laid down in this Policy.

7.3.3 If any difficulty arises in the implementation of the schemes/ plans, the matter shall be referred to the Central Government in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources) for its decision and the decision of the Central Government shall be binding on the concerned States and Union territory.

CHAPTER - VIII

MONITORING MECHANISM

8. NATIONAL MONITORING COMMITTEE

National Monitoring Committee

8.1 The Central Government, Ministry of Rural Development, Department of Land Resource shall constitute a National Monitoring Committee, to be chaired by the Secretary, Department of Land Resources for reviewing and monitoring the progress of implementation of resettlement and rehabilitation scheme/plan relating to all projects to which this Policy applies. The Committee will have the following or his nominee not below the rank of Joint Secretary as its members:

Secretary, Planning Commission
Secretary, M/o Social Justice and Empowerment
Secretary, M/o Water Resources
Secretary, M/o Tribal Affairs
Secretary, M/o Railways
Secretary, M/o Power
Secretary, M/o Coal

Besides, the Secretary of the administrative Ministry/Department of the project for which the land is to be acquired shall be invited as one of the Members. The functions and duties of this Committee shall be prescribed by this Ministry.

8.2 The National Monitoring Committee shall be serviced by the National Monitoring Cell to be constituted by the Department of Land Resources for reviewing and monitoring the progress of implementation of Resettlement and Rehabilitation scheme/plan relating to all projects to which this Policy applies.

**National
Monitoring
Cell**

8.3 National Monitoring Cell constituted under this Policy shall be headed by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India. The National Monitoring Cell as referred to above shall be assisted by the officers and staff as referred to in **Annexure- I**.

APPLICABILITY**Applicability**

8.4 The National Policy on Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families (NPRR – 2003) shall come into effect from the date of its publication in the Gazette of India (Extra-ordinary).

ANNEXURE – I

THE COMPOSITION OF THE NATIONAL MONITORING CELL
(See Para 8.3)

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post
1.	Joint Secretary, Resettlement and Rehabilitation	1
2.	Zonal Directors/Subject Matter Specialist/ Consultant	4
3.	Deputy Director	4
4.	Statistical Officer	1
5.	Section Officer/Desk Officer	1
6.	Assistant	2
7.	Statistical Assistant	2
8.	L.D.C-cum-Typist	4
9.	Stenographer	9
10.	Peon	4
11.	Sweeper	2
12.	Driver	2

LALITHA KUMAR, Jt. Secy.